प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 21/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर सिफारिशें जारी की

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 अगस्त, 2019 को भादूविप्रा को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1) (क) के तहत एफएम चरण–3 नीति के तहत 283 शहरों (260 नए + 23 वर्तमान) के लिए नए आरक्षित मूल्य पर सिफारिशें प्रस्तुत करने, 2011 से 2015 तक के वर्षों में निर्धारित आरक्षित मूल्यों के सूचीकरण और मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

3. भादूविप्रा ने 16 अक्टूबर 2019 को "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर एक परामर्श पत्र जारी किया और एमआईबी के पत्र में सूचीबद्ध मुद्दों पर हितधारकों से सुझाव मांगे। टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2019 थी और प्रति–टिप्पणियों के लिए 13 नवंबर 2019 थी। भादूविप्रा को 10 टिप्पणियां मिलीं। सभी टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद, विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए, दिल्ली में 8 जनवरी 2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के आगे का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क) 273 नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों के मूल्य निर्धारण को, तीन मूल्यांकन दृष्टिकोणों के साधरण औसत के रूप में निकाला गया। दृष्टिकोण निम्नलिखित चर पर आधारित हैं:

- शहर की जनसंख्या
- प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)
- एफएम रेडियो के श्रोतागण
- मौजूदा एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा अर्जित प्रति व्यक्ति सकल राजस्व

ख) 273 नए शहरों में से प्रत्येक के लिए एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में स्थित शहरों, जिसके संबंध में प्रत्येक शहर के लिए मूल्यांकन का 40 प्रतिशत तय किया गया है, को छोड़कर प्रत्येक शहर के लिए मूल्यांकन का 80 प्रतिशत तय किया गया है।

ग) 273 नए शहरों में एफएम रेडियो के लिए अनुशंसित आरक्षित मूल्य अनुलग्नक–1 में दिए गए हैं।

घ) 'अन्य' श्रेणी के 10 शहरों के लिए, जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख से कम आबादी वाले, प्रत्येक शहर के प्रत्येक चैनल के लिए आरक्षित मूल्य 5 लाख रुपये तय किया गया है।

ड.) एफएम रेडियो की नीलामी में भाग लेने के लिए इस तरह के अनुमति धारक को बाहर रखने के लिए देश में कुल एफएम रेडियो चैनलों की मौजूदा 15 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

च) चरण–III के शेष चैनलों की नीलामी उन्हें प्रौद्योगिकी से डीलिंक करके किया जाना चाहिए। प्रसारकों को भविष्य में नीलामी के माध्यम से उन्हें आवंटित आवृत्ति पर रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी तकनीक (एनालॉग या डिजिटल या दोनों) का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

छ) यदि रेडियो प्रसारणकर्ता डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवंटित आवृत्ति पर तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन एक से अधिक चैनल प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5. सिफारिशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।